

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1966 (ज्येष्ठ 28, 1888)

No. 25]

NEW DELHI SATURDAY, JUNE 18, 1966 (JYAISTHA 28, 1888)

इस भाग में भिन्न गृह संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

घोषित

NOTICE

नीचे विधे भारत के असाधारण राजपत्र 2 जून 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 2nd June 1966 :—

क्र.सं. Serial No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
92	No. P.N. (U.K. Licensing) 3 of 1966, dated 30th May 1966.	Min. of Commerce	Scheme for licensing of cotton textiles export to the U.K. from India, quota for 1965.
93	No. 68-ITC (PN)/66 dated 30th May 1966.	Do.	Import policy for actual users for the year April 1966— March 1967—issue of advance licences for raw materials components and spares.
94	No. 69-ITC (PN), 66 dated 2nd June 1966.	Do.	Import of machinery components thereof equipment, other commodities and raw materials from the U.S. under AID Non-Project Loan.
	No. 70-ITC(PN) 66 dated 2nd June 1966	Do.	I.T.C. classification of Hides and Skins, raw or salted with woolen.

ऊपर विधे असाधारण राजपत्रों की प्रतिमा प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

(CONTENTS)

पृष्ठ (Page)	पृष्ठ (Page)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय का छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधेतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं .. 443	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधेतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं .. —
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय का छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी बफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंधित अधिसूचनाएं .. 529	भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई बफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंधित अधिसूचनाएं .. 355
	भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम —
	भाग II—खंड 2—विधेतर और विधेतरों समर्थी प्रार रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट —

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, नियम आदि सम्मिलित हैं)	1047	भाग III—खंड 2—एकत्र कार्यलय, कश्मिरा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	227
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1699	भाग III—खंड 3—मुक्त प्रांतों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	71
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	159	भाग III—खंड 1—विधिक विचारों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	421
भाग III—खंड 1—महासेवापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	387	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	131
		पूरक सं० 25—	
		11 जून 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	855
		21 मई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक भावार्थी के शहरों में जन्म, तथा सभी वामारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े	867
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	
	443		1699
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court		PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	
	529		159
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	
	—		387
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	
	355		227
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
	—		71
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills		PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	
	—		421
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (I)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)		PART IV—Advertisement and Notices by Private Individuals and Private Bodies	
	1047		131
		SUPPLEMENT No. 25—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 11th June 1966	
			855
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 21st May 1966	
			867

भाग I—खण्ड

PART I—SECTION 1

(यह भाग प्रकाशित होकर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Government of India (as far as the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

गृह-मंत्रालय
नियम

गई दिल्ली दिनांक 18 जून 1966

सं० 15/2/66-ए० आर्डी० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवंबर 1962 के बाद सगस्त्र सेना में कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिए अक्टूबर 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

- (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा,
- (ii) भारतीय विदेश सेवा,
- (iii) भारतीय पुलिस सेवा,
- (iv) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) श्रेणी I,
- (v) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,
- (vi) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,
- (vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
- (viii) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी I),
- (ix) भारतीय जल-संचयन प्रकृति सेवा, श्रेणी I, (सहायक प्रबंधक-सौर-तकनीकी),
- (x) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I,
- (xi) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,
- (xii) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैंड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी I,
- (xiii) भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना का परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग,
- (xiv) डिग्री, डिप्लोमा प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा, श्रेणी II,
- (xv) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुष्ठान अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II,
- (xvi) सीमा-गुल्म मूल्य-निश्चयन (एग्जचर) सेवा, श्रेणी II,
- (xvii) विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा, श्रेणी II,
- (xviii) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधि-तरी ग्रेड, श्रेणी II,
- (xix) वेल्स बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II, और
- (xx) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैंड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी II

उम्मीदवार आयुक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठ सकते हैं। वह इन सेवाओं में से किसी सेवाओं के लिए पदों की प्राप्ति में बैठना चाहते हैं। उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में करेंगे। उम्मीदवारों को सेवाओं की प्राप्ति है कि किसी भी ऐसी सेवा में

उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन-पत्र में नहीं करेंगे।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन सेवाओं के अधिमान-क्रम का स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दें जिनके लिए वे प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इन सेवाओं के अधिमान-क्रम में परिवर्तन करने के लिए केवल उन्हीं प्रार्थनाओं पर विचार किया जाएगा जो 31 दिसंबर 1966 को या उसके पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय या गृह मंत्रालय में पहुंचेंगी, इसके बाद पहुंचने वाली किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित स्थायी रिक्तियों पर निम्नलिखित रूप में नियुक्तियों की जाएंगी :

सेवा	कितनी प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं
(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा	20%
(ii) भारतीय पुलिस सेवा	30%
(iii) केन्द्रीय सेवाएं/पद, श्रेणी I, (गैर-तकनीकी) (इसमें रेलवे की सेवाएं/पद भी सम्मिलित हैं)	25%
(iv) केन्द्रीय सेवाएं/पद, श्रेणी II, (गैर-तकनीकी) (इसमें रेलवे की सेवाएं/पद भी सम्मिलित हैं)	30%

परंतु भर्ती के किसी भी वर्ष में इस परीक्षा के संबंध में निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए, और निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए, आरक्षित रिक्तियों की कुलसंख्या नीचे बताई गई सीमा से अधिक नहीं होगी :—

- (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाएं/श्रेणी I के पद (गैर-तकनीकी) के मामले में कुल स्थायी रिक्तियों की 45% रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी।
- (ii) भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं/श्रेणी II के पद (गैर-तकनीकी) के मामले में कुल स्थायी रिक्तियों की 30% रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विनियम 1965 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति प्रविषा (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान, (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. वे सभी आपातकालीन आयुक्त अफसर/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसर इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिन्हें 1 नवंबर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त हुआ था और जो निर्मुक्त हो चुके हैं या 1967 में निर्मुक्त होने वाले हैं बशर्ते कि वे इन नियमों में विहित अहंताएं/शर्तें पूरी करते हों।

5 (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(ii) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या
- (ख) सिक्किम की प्रजा, या
- (ग) नेपाल की प्रजा, या
- (घ) भूटान की प्रजा, या
- (ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या
- (च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और कीन्या, उगांडा, टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परंतु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आनेवाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

- (i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और तब से आम तौर से भारत में रह रहे हों।
- (ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लिया हो।
- (iii) ऊपर की (च) कोटि के वे शैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार

नौकरी कर रहे हैं और उनके सेवा काल का क्रम नहीं टूटा है। तब तक यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद उनके सेवा द्वारा शुरू की हो तो उसे भी औरो की तरह पात्रता-प्रमाण पत्र देना होगा।

एक और शर्त यह है कि उम्मीदवार (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार पात्रता प्रमाण-पत्र के बिना केवल के पास नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उन उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ अन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार वे जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया था उस वर्ष के 1 अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है :—

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष ;
- (ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;
- (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;
- (iv) यदि उम्मीदवार सब राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;
- (v) यदि उम्मीदवार अक्टूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;
- (vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्टूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;
- (vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के सब राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;
- (viii) यदि उम्मीदवार, कीन्या, उगांडा, तथा टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;

- (ix) यदि उम्मीदवार 1 जून 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;
- (x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;
- (xi) रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष; और
- (xii) रक्षा सेवाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों के मामले में जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जातियों के हों अधिक से अधिक आठ वर्ष।

उपयुक्त परिस्थिति को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू होगा।

परंतु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाएगी जो उस वर्ष के 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया था, उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया था उसके बाद के वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का हो गया था।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता-परीक्षा में भाग ले चुका है।

8. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के पहले वाले वर्ष की परीक्षा में बैठना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वाले वर्ष की परीक्षाओं में बैठना चाहिए।

9. सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करते समय उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में दिए हुए किसी विश्वविद्यालय की उपाधि या परिशिष्ट I-क में उल्लिखित कोई अर्हता होनी चाहिए।

परंतु भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करते समय उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता या परिशिष्ट I-ख में उल्लिखित कोई अर्हता होनी चाहिए।

नोट 1—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने के समय उपर्युक्त कोई अर्हता नहीं थी परंतु उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास कर ली थीं जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

2—यदि कोई उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करते समय अन्य शर्तें पूरी करता था, किन्तु उसने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली थी जो परिशिष्ट I में सम्मिलित नहीं है तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

10. यदि इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार को नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में हो जाती है तो वह इसके बाद वाला किसी और परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार को नियुक्ति नीचे स्तंभ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा के बाद की किसी परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तंभ (iii) में दी हुई हैं :—

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है
----------	---------------------------	---

(i)	(ii)	(iii)
1. भारतीय पुलिस सेवा		भारतीय प्रशासनिक सेवा, और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I।
2. केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I, भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर		भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।
3. केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी II, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा।		भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I।

11. उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपने यूनिट की कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दे, वह उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज देगा।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (मर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) (i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी शाखा-कार में उपस्थित होने से, तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, सरकार के अन्तर्गत नौकरियों में, उसको सहा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए वांछित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अर्थात् अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (qualifying marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता-प्राप्त समझेगा, उन्हें उन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे, तो उसकी उस सेवा में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

18. (क) यदि परीक्षा फल के आधार पर, निर्भुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों का भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जाएगा।

(ख) यदि अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, निर्भुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी, तो जो व्यक्ति नियुक्त नहीं हुए हैं उनके नामों को आगामी वर्ष (वर्षों) में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के नियतांश (quota) के अनुसार नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा-सूची (सूचियों) में रख दिया जाएगा।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

20. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय जो अपना अधिमान-क्रम (preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा, परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिए वह उम्मीदवार हो।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो किसी बाद की परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तंभ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो किसी बाद की परीक्षा के परिणामों के आधार पर उस सेवा के सामने नीचे स्तंभ (iii) में उल्लिखित सेवाओं के लिए ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
(i)	(ii)	(iii)
1	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I।
2	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।
3	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी II, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा तथा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी I।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट— बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में इन नियमों के परिशिष्ट IV में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में इन मानकों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

23. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए, तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों की जाती हैं, तब तक प्राप्त नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

24. भारतीय विदेश सेवा की शाखा "क" में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

ओ० सं० मारवा, अवर सचिव

परिशिष्ट I

(नियम 9 के परंतुक के अनुसार)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से निर्गमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिए जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय।

इंग्लैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्कॉटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एवरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और संत एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. फांसीसी परीक्षा (Baccalaureat)।
2. फांसीसी परीक्षा (Propedentique)।
3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कॉमन ऑफ़ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
4. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
5. आन्ध्र भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया कॉमन फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा।
6. ग्रहिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा।
7. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पॉडिचेरी का 'उच्च पाठ्यक्रम' यदि 'पूर्ण छात्र' (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।
8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

परिशिष्ट I-ख

भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व सहायता के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभागों की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची।

(i) इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंजीनियर्स भारत की सह-सदस्यता (एम्पायमेंट मेम्बरशिप) परीक्षा के खण्ड 'क' और 'ख' में उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए जिनके होने पर इन खण्डों में उत्तीर्ण होने से छूट मिली हुई हो या बाद में मिल जाए; अथवा

(ii) भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस) बंगलोर की सह-सदस्यता (एम्पायमेंटशिप) या कैलेशिप; अथवा

(iii) लौबरो कालेज, लेस्टरशायर से सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में आनर्स डिप्लोमा, वशत कि ऐसा उम्मीदवार या तो सामान्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो या उसे उससे छूट मिली हो; अथवा

(iv) वह इंस्टीट्यूशन ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स (इंडिया) में स्नातक सदस्यता परीक्षा (ग्रेजुएट मेम्बरशिप एग्जामिनेशन) में उत्तीर्ण हों; अथवा

(v) नवम्बर 1959 के बाद की इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लन्दन) की स्नातक सदस्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हों।

इंस्टीट्यूशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लन्दन) की नवम्बर 1959 से पहले की गई स्नातक सदस्यता परीक्षा भी नीचे लिखी शर्तों पर मान्य है :—

(1) नवम्बर, 1959 से पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार निम्नलिखित अतिरिक्त विषय लेकर परीक्षा में बैठें हों और उत्तीर्ण हुए हों :—

(i) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी के सिद्धांत और प्रयोग (1959 के बाद की योजना के खण्ड 'क' में बताए गए पाठ्य-विवरण के अनुसार)

(ii) गणित II (1959 के बाद की योजना के खण्ड 'ख' में बताए गए पाठ्य विवरण के अनुसार)

(2) संबंधित उम्मीदवार Institution of Electronics and Radio Engineers (London) से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेकर पेश करें कि वे ऊपर (1) में बनाई शर्तें पूरी करते हैं।

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूपरेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तान विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है। इसके पूर्णांक 450 होंगे।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा। इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत्ती के मूल्यांकन के लिए रखे जाएंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(i) निबंध	3 घंटे	150
(ii) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	150
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही लगे जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपर्युक्त विषयों के लिए होंगे।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ में लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इस के लिए उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

8. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसलिए काट लिए जाएंगे कि वही सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभाव-पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग—क

(परिशिष्ट II के पैरा 3 के अनुसार)

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिए कई विषय दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिन से उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अंतर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप मार-लेखन के लिए लेखों दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उनके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—ख

मौखिक परीक्षा—एक बोंड उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा लेगा। इस बोंड के सामने प्रत्येक उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा जिसमें सशस्त्र सेना में की गई सेवा भी सम्मिलित होगी। उम्मीदवार से सामान्य रुचि की बातों और सशस्त्र सेना में उसके अनुभव पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह मौखिक परीक्षा इस उद्देश्य से ली जाएगी कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षक यह निर्णय कर सकें कि

उम्मीदवार ने जिन सेवाओं के लिए आवेदन किया है, उनके लिए वह उपयुक्त है या नहीं।

मौखिक परीक्षा में पूरी तरह से प्रति-परीक्षा (Cross-Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। यह एक स्वाभाविक बातलाप है, किंतु यह एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार के मानसिक गुणों, जैसे मानसिक सतर्कता और पहल-शक्ति, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कमंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, का उद्घाटन करना है।

परिशिष्ट III

इस परिशिष्ट में सेवा की उन शर्तों का संक्षेप में वर्णन किया गया है जो नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों पर लागू होंगी। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का प्रवर्तन-क्रम और वेतन भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा**—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतन-मानः—

जूनियर—50 400-400-500-40-700-कु० रो०-30-1000 (19 वर्ष)।

सीनियर

(i) समय-मान रु० 900 (छठे या पहले)-50-1000-60-1600-50-1800 (25 वर्ष)।

(ii) सलेक्शन ग्रेड—1800-100-2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होने हैं जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

मंहगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय मान में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(घ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) **डाक्टरों परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरों परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरों परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप कंसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सब्टेंडेंट पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिये उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या, यदि उसका कोई मूल पद हो, तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) **वेतन-मान**—

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-रु० १०-30-1000

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)-50-1000-60-1600-50-1800

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1,800 से रु० 3500, तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख-अवधि परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि को, समय-मान में वेतन वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब कि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हों) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा।

91GI/66

विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे, जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन निर्वाह के बड़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और जातिस्थ (इंस्टैटनमेंट) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी:—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।

(ii) सहायता-प्राप्त डाक्टरों परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरों परिचर्या की सुविधाएं।

(iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा-भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (outfit allowance) अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिये छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933, कुछ तरमियों के साथ, इन सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवा-निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (liberalised) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. भारतीय पुलिस सेवा— (क) नियुक्त परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। मफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख), (ग)
(ग) } और (घ) में दिया गया है।
(घ) }

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-
रु० री०-35-950

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-
1250-50-1300

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उपमहानिरीक्षक—रु० 1000-100-1800

पुलिस कमिशनर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800-200-
2000

पुलिस महा-निरीक्षक—रु० 2250

निवेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 2750

सहगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (छ),
(ज) } (ज), (अ) और (आ) में दिया गया है।
(अ) }
(आ) }

4. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी II:

(क) नियुक्तियों की वी के विवे परीक्षाधीन रहेगी जो समय प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखार्थी अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पत्रका कर दिया जाएगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस/खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) वेतन-मान—

ग्रेड I—(सलेक्शन ग्रेड)—रु० 900 (नियत)

ग्रेड II समय-मान—रु० 300-25-475-रु० री०-25-650-
रु० री०-30-800

प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतन-मान में कम-से-कम वेतन मिलेगा।

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1965 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारी उसी दर से सहगाई भत्ता और सहगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी।

(छ) सहगाई भत्ते के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहचान स्थानों तथा गृहस्थानों में रहने-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें इप्टी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाए और उन स्थानों के लिये वे भत्ते अनुमत्य हों।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनु रूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी I):

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के अन्तर्गत वे सभी पद आते हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisations) में हैं और जिनके लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं:

ग्रेड	वेतन-मान
श्रेणी I	
सलेक्शन ग्रेड	रु० 2250 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800-100-2000
(जूनियर मान)	रु० 1600-100-1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300-60-1600
(जूनियर मान)	रु० 1100-50-1400
ग्रेड I	रु० 700-40-1100-50/2-1250
ग्रेड II	रु० 400-400-450-30-600-35- 670-रु० री०-35-950
श्रेणी II (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350-25-500-30-590-रु० री०-30-800
श्रेणी II (अराजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270-10-290-15-410-रु० री०-15-485

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में, नीचे बताई गई प्रतिशतता के अनुसार खाली जगहों में खोली भर्ती की जाती है:—

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	12%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II	50%
ग्रेड IV	100%

उपरोक्त ग्रेडों की बाकी खाली जगहें और सैनिक ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर मान) और ग्रेड III की खाली जगहें भी, ठीक निचले ग्रेडों के ड्यूटी पदों (Duty Posts) पर काम करने वाले अधिकारियों में से चुने गए व्यक्तियों की परीक्षा कर के भरी जाएंगी।

(घ) (i) ग्रेड में सीधे भर्ती होने वाले अधिकारी दो वर्ष तक परख पर रखे जाएंगे। परख अवधि में उन्हें इन्स्ट्रुट आक माना कम्प्यूटेशन, किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एकादमी तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की पूरी अवधि 15 महीने की होगी। प्रशिक्षण के स्वरूप और अवधि में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी में "पाठ्य प्रमाणा परीक्षा" तथा एक विभागीय परीक्षा पास करनी होगी जिसमें भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रशिक्षण की अवधि में विभागीय परीक्षा पास न कर सका तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या यदि वह किसी गलत पद पर रहता (Lien) रखता हो तो उसे उस पद पर वापस भेजा जा सकता है।

(ii) परख-अवधि की समाप्ति पर, यदि रणायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है। यदि परख-अवधि अधिकारी का कार्य और आचरण असंतोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ाया जा सकता है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसके कार्य और आचरण से उसके कार्य क्षम होने की संभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरा की पाठ्यप्रमाणा परीक्षा पास नहीं करता तो एक साल के लिए उसका वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभाग में नियमों के अनुसार उसका दूसरा वेतन वृद्धि जब पड़ने वाला हो, और इन दोनों में जो पहले पड़े, तब तक वेतन वृद्धि स्थगित रहेगा।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशेष अवधि तक संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहाँ तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

7. भारतीय समाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि

परख-अवधि अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आचरण पक्का किए जाने (Confirmation) के समय सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष का अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यक्षम होने का संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्ति होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकते/सकता है या यदि, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकते/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकते/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने और अन्य सुधार किए जाने का संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रों और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत स्वायत्त लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रों तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप से रहना पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ला जा सकता है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फ़ाउंड सर्विस) पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतन-मान :

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा—इस सेवा का समय—

मान—र० 400-400-450-30-510-कु० र० 700-40-1100-50/2-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—र० 1300-60-1600।

महालेखापाल—र० 1300-100-2000-125-2250।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों का सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के लिए, उनका सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिना जाएगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 र० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगे।

नोट 3—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरा की पाठ्य-प्रमाणा परीक्षा पास नहीं करता तो र० 450 तक ले जाने वाला उसका वेतन वृद्धि की तारीख एक साल के लिए अथवा तब तक जब कि विभागीय नियमों के अनुसार उस दूसरा वेतन-वृद्धि

होने वाली हो, और इन दोनों में से जो भी पहले पड़े, स्थगित रहेगी।

समय मान :

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक,
श्रेणी I

₹ 400-400-450-30-510-
कु० रो० 700-40-1100-50/
2-1250।

उत्पादन शुल्क सहायक समाहर्ता,
सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता

सीमाशुल्क उपसमाहर्ता

उत्पाद शुल्क उपसमाहर्ता

सहायक निदेशक

उपनिदेशक

अपील के अपर समाहर्ता

सीमाशुल्क समाहर्ता

उत्पाद शुल्क समाहर्ता

₹ 1100-50-1300-60-1600।

₹ 1800-100-2000-125-2250।

नोट I—भारतीय सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क सेवा के श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी ₹ 400-400-450-30-510-कु०-रो०-700-40-1100-50/2-1250 के निर्धारित वेतन मान में वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग/सीमाशुल्क विभाग/स्वायत्त विभाग में विभागीय प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी में आधारभूत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के बाद पाठ्यक्रमान्त परीक्षा उन्हें पास करनी होगी। उन्हें विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा और विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर ₹ 450 कर दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा का खण्ड II पास कर लेने के बाद उनका वेतन ₹ 480 के स्तर पर निश्चित कर दिया जायगा। ₹ 480 के ऊपर वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उन्होंने 4 वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो या ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो कि आवश्यक समझी जाय।

2. यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता तो उसकी पहली वेतन वृद्धि जिस तारीख को मिलने वाली थी उसके बाद तक स्थगित कर दी जायगी। अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत जब भी उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़ेगी तब तक स्थगित रहेगी।

नोट II—परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और वे इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय-मान :—

₹ 400-400-450-480-कु० रो०-700-40-1100-
1100-1150-1150-1200-1200-1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

₹ 1300-60-1600

₹ 1600-100-1800 (सनेक्शन ग्रेड)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

₹ 1800-100-2000-125-2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—₹ 2750 (नियत)

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के लिए, उनकी कार्य ग्रहणी तारीख से गिनी जाएगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 ₹ से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होती उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी-1 (क) नियुक्ति पर ख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुये उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का पर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खंडों में उल्लिखित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन-मान :

आय-कर अधिकारी, श्रेणी-I

₹ 400-400-450-30-510-कु० रो०-700-40-1100-
50/2-1250।

आयकर सहायक आयुक्त—₹ 1100-50-1300-60-
1600।

आयकर आयुक्त—₹ 1800-100-2000-125-2250।

(च) परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर ₹ 450 कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर ₹ 480 कर दिया जाएगा। ₹ 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन-वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा उस तारीख तब जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1.—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2.—परखाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए कि, उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (गैर-तकनीकी संवर्ग)

नियुक्तियां सहायक प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जाएंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण देना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवार को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा।

सहायक प्रबन्धक, जिनका पुनरीक्षित वेतनमान इस प्रकार है रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950 अपनी योग्यता (merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

वेतन-मान

1. उप-प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी	रु० 700-40-1100- 50/2-1250
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी	रु० 1100-50-1400
3. सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड II)	रु० 1300-60-1600
4. सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड I)	रु० 1600-100-1800
5. उप-महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरी।	रु० 1800-100-2000

11. भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I)

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुये उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे उत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार को किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन-मान :—

समय-मान रु० 400-400-450-30-510-कु० रो० 700-40-1100-50/2-1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय मान में वेतन लेगे)।

डाक सेवा निदेशक : रु० 1300-60-1600

महा पोस्टमास्टर : रु० 1800-100-2000

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250

(च) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी रु० 400-400-450-30-480-510-कु० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग का विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक, एकादमी, मसूरी के आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखार्धान अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जाएगा। समयमान के अंतर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दो जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I, के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

12. भारतीय रेलवे सेवा—

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा।

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकांर्यों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियाँ हों और अधिकारी का वायें ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। हालाँकि दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊँची तथा नीची विभागीय परीक्षाएँ पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों का ध्यान में रखते हुये, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुये उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(झ) वेतन-मान :—

(क) जूनियर रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950—(प्राधिकृत मान) सीनियर रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40-1100-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)। जूनियर प्रशासनिक मान रु० 1300-60-1600 (प्राधिकृत मान) सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800-100-2000-125-2250 (प्राधिकृत मान)।

(ख) नियुक्ति होने पर, परखाधीन अधिकारी को एक करार करना होगा जिसके द्वारा वह अपने आप को और एक जमानतदार को, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, इस बात के लिए आबद्ध करेगा कि यदि वह केन्द्रीय सरकार के लिए संतोषप्रद रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त नहीं कर सका तो परखाधीन अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के परिणाम स्वरूप उसे जो नुक़में दी गई होंगी उन्हें वह वापस कर देगा।

(ग) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएँ पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उस वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएँ पास कर लेगा, त्यों ही उसकी रु० 400-950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से 480 की अग्रिम वृद्धियाँ मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियाँ मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुये, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएँ पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन समयमान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

13. सैनिक भूमि और छ.वर्ग सेवा (श्रेण: I और श्रेण: II)

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आम तौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिस की अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुये उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो

तो सरकार अपने निर्णय में या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसका परख-अवधि का, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायगा।

(घ) यदि ऊपर उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जायगी और दोनों में से बिनी भी और से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि, देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मम्बूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जायगी अथवा विभागीय स्तरों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होगी वार्षिक हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतन-मान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

- (i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियाँ।
रु० 1800—100—2000।
- (ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियाँ।
रु० 1600—100—1800।
- (iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियाँ।
रु० 1300—60—1600।
- (iv) सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियाँ।
रु० 1100—50—1400।

श्रेणी I

- (v) उप-सहायक निदेशक, रु० 400—400—450—
सैनिक भूमि और 30—510—कु० रो०—
छावनियाँ, सैनिक संपदा 700—40—1160—
अधिकारी और कार्यपालक 50/2—1250।
अधिकारी

श्रेणी II

- (vi) कार्यपालक अधिकारी रु० 350—25—500—30—
590—कु० रो०—30—
800—कु० रो० 830—
35—900।

- (vii) सहायक सैनिक संपदा रु० 350—25—500—30—
अधिकारी 590—कु० रो०—
30—800—कु० रो०—
830—35—900।

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को सामान्यतया, उप-सहायक निदेशक सैनिक संपदा अधिकारी, और श्रेणी I और श्रेणी II को उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया जायगा जिन पर छावनी अधिनियम, 1924 की धारा—13 की उपधारा—(4) के खण्ड (ड) का उप-खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया उन छावनियों में नियुक्त किया जायगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं है।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियों, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by selection) की जायेगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी II से श्रेणी I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I में तब तक पदोन्नति नहीं किया जायगा जब तक कि श्रेणी II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(अ) समय-समय पर रणशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होंगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

14. भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना का परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग

(क) नियुक्ति के लिये चुने गए उम्मीदवारों को परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभागों में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ड) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करता होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायगी तो उनके अनुसार परख की कुल अवधि भी बढ़ जायगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग का परखाधीन अधिकारी, परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकम वापस करना होगा।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियाँ परख पर की जायेंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त

कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षाएं नियमतः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाएं। क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतनवृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिए जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन वृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) नियुक्ति होने पर, परखाधीन अधिकारी को एक करार करना होगा जिसके द्वारा वह अपने आपको और एक जमानतदार को, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, इस बात के लिए आबद्ध करेगा कि यदि वह केन्द्रीय सरकार के लिये संतोष-प्रद रूप से अपनी परख अवधि समाप्त नहीं कर सका तो परखाधीन अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति के परिणाम स्वरूप उसे जो रकम दी गई होगी, उन्हें वापस कर देगा।

(ङ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही या परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई दूसरी समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(च) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (धातायात) और धाणिज्य विभाग के अधिकारी (परखाधीन) भी —

(क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(छ) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा। वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जायगी।

(ज) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जायगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी।

(झ) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि भर उसी रेलवे में रखा जायगा जिस में वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जायेंगे और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह

अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सके।

(ञ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की आपेक्षिक वरीयता (रिलेटिव सीनियारिटी) आम तौर पर, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जायेगी। यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियारिटी) भी घट सकेगी। वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है। उस को यह भी अधिकार है कि वह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है।

(ट) वेतन-मान—

जूनियर:—रु० 400-400-450-30-600-35-670
कु० रु०-35-950 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर:—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100
-50/2-1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड:—रु० 1300-60-1600
(प्राधिकृत मान)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड:—1800-100-2000-125-
2250 (प्राधिकृत मान)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उस की वेतन-वृद्धि रोक दी जायेगी और परख-अवधि बढ़ा दी जायेगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जायेगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बाकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उस को रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अविध पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2 —जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका

वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जायगा।

(ठ) वेतन-वृद्धियाँ केवल अनुमोदित सेवा के लिए ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(ड) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति स्थापना (Establishment) में खाली जगह होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुनाव (Selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसी पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता।

(ढ) परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियाँ हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इस में महा-प्रबन्धकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिये।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष।

विषय	अवधि
	मास
1. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	4
2. एरिया स्कूल, गार्ड की ब्यूटी सीखने के लिये	1
3. गार्ड का काम	$\frac{3}{4}$
4. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर	3
5. टिकट घर, पार्सल कार्यालय, माल-भोदाम और यानाम्परण ग्रेड	1
6. यातायात लेखा कार्य, जिसमें दौराकार लेखानिरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है	$1\frac{1}{2}$
7. एरिया स्कूल में, सहायक स्टेशन मास्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिये	1
8. यार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन और गाड़ी परीक्षक का काम	3
9. सहायक लोको फोरमैन का काम	$\frac{1}{2}$
10. सहायक नियन्त्रक का काम	2
11. बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण (दूसरा दौर)	$1\frac{1}{2}$

विषय	अवधि
12. (क) डिस्ट्रिक्ट या डिबिजन कार्यालय में प्रशिक्षण	मास 1
(ख) सहायक बिजली नियन्त्रक का प्रशिक्षण	$\frac{1}{2}$
13. मुख्यालय (परिचालन कार्यालय) में प्रशिक्षण	$1\frac{1}{2}$
14. मुख्यालय (वाणिज्य कार्यालय) में प्रशिक्षण	$1\frac{1}{2}$
	23 $\frac{1}{2}$
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य छुट्टियों के लिये नियत की गई अवधि	$\frac{1}{2}$
कुल	24 मास

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जायेगा। परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियन्त्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्यों के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाये और योग्य घोषित किया जाये।

15 केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, ग्रेड II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है:—

ग्रेड	वेतन-मान
सलेक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	₹ 1100-50-1300-60-1600-100-1800.
ग्रेड I अवर सचिव	₹ 900-50-1200.
अनुभाग अधिकारी ग्रेड	₹ 350-25-500-30-590-कुं० रो० 30-800-कुं० रो० 30-830-35-900.
सहायक ग्रेड	₹ 210-10-270-15-300-कुं० रो०-15-450-कुं० रो०-20-530.

सलेक्शन ग्रेड और ग्रेड I का नियन्त्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया, "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को, सामान्यतया, शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिन में एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड I में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलेक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे।

16. सीमाशुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी II

(क) निर्धारित वेतन मान रु० 350-25-500-30-590-कु० रो० -30-800-कु० रो०-830-35-900 है। इस सेवा में सीधे भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख-अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकने पर या परीक्षा पास न कर सकने पर, परखाधीन अधिकारियों को सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) परख-अवधि के समाप्त होने पर और विभागीय-परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर, अधिकारी पक्के किये जा सकेंगे, यदि स्थायी पद उपलब्ध होंगे। यदि सम्बन्धित सीमाशुल्क समाहर्ता की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी परख-अवधि उतनी बढ़ाई जा सकती है जितनी कि सम्बन्धित सीमाशुल्क समाहर्ता उचित समझे।

(ग) मूल्य-निरूपक के रूप में सेवा की अवधि समाप्त होने पर अधिकारी रु० 600-35-950 के वेतनमान में प्रधान मूल्य-निरूपक के ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हो जायेंगे और उसके बाद वे सहायक समाहर्ता, श्रेणी I के पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे।

(घ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझे जायेंगे।

नोट—ऊपर दिए गए वेतन और ग्रेड बदले जा सकते हैं।

17. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके

कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतन-मान:—

ग्रेड I — (सलेक्शन ग्रेड) — रु० 900—50—1200 ।

ग्रेड II — रु० 300—30—510—कु० रो०—30—600—40—720—कु० रो० —40—800—50—850 ।

प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेतन मिलेगा।

उक्त सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

(च) उक्त सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें इयूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत दिये गए आदेशों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनु रूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतन-मान हैं:—

सेवा	वेतन-मान
(i) सहायक निदेशक/अधर सचिव	रु० 900—50—1250 ।
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350 —25 — 500 — 30—590—कु० रो०— 30—800—कु० रो०— 30—830—35—900
(iii) सहायक	रु० 210—10—270—15 300—कु० रो०— 15—450—कु० रो०— 20—530 ।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जाएगा। इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जाएगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊँचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिए पात्र होंगे।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किए जा सकते हैं।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket Order) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ञ) इन नियमों के अंतर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अंतर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

18. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख', अनुभाग अधिकारी ग्रेड श्रेणी II

(क) भारतीय विदेश सेवा, शाखा—'ख' (श्रेणी II) के समेकित ग्रेड II और III की 25% अनुरक्षण संबंधी खाली जगहें (maintenance vacancies) संघीय लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। इस ग्रेड का वेतनमान रु० 350—25—500—30—590—रु० १०—30—800—रु० १०—30—830—35—900 है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में सीधे भर्ती होने वाले अधिकारी दो वर्ष तक परख पर रहेंगे। इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परखाधीन-अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या निर्धारित परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) परख-अवधि समाप्त होने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हुए तो सरकार, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परख की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी, सामान्यतया, अनुभागों के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उन्हें जब विदेश मंत्रालय/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुख्यालय में लगाया जाएगा तो उन्हें अनुभाग अधिकारी और कमी-वभी प्रशासन अधिकारी का पदनाम दिया जाएगा। जब वे विदेश स्थित भारतीय मिशन में काम करेंगे तो वे रजिस्ट्रार कहलाएंगे, यद्यपि स्थानीय प्रयोजनों के लिए, उन्हें राजनयिक हैमियत वाले 'सहचारी' (अताचे) कहा जा सकता है।

(च) पदोन्नति के संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, अनुभाग अधिकारी, रु० 900—50—1250 के वेतन-मान में भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I में पदोन्नति पा सकते हैं।

(छ) इस संबंध में, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I के अधिकारी बारी आने पर रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50—1000—60—1600—50—1800 के वेतन-मान में भारतीय विदेश सेवा (क) के सीनियर वेतनमान के पदों पर नियुक्ति पा सकेंगे।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है और इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों को सामान्यतया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को छोड़ कर अन्य किसी मंत्रालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाता। परन्तु उनसे भारत में या भारत से बाहर कहीं पर भी सेवाएं ली जा सकती हैं।

(झ) विदेश में सेवा करने की अवधि में भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त विदेश भत्ता भी मिलेगा जिसकी दर, समय-समय पर, संबंधित देशों में जीवन-निर्वाह के खर्च को ध्यान में रखते हुए मंजूर की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू की गई भारतीय विदेश सेवा (P.L.C.A.) नियमावली 1961 के अनुसार निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

- (i) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान (Free furnished Accommodation)
- (ii) सहायताप्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना के अंतर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं।
- (iii) भारत आने के लिए और वापस विदेश में अपने कार्य-स्थल पर जाने के लिए हवाई यात्रा का किराया, जो अधिकारी की पूरी सेवा-अवधि में अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों में ही

दिया जाएगा, जैसे—सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या सख्त बीमारी, जो भारत में रहता हो।

- (iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लंबी छुट्टियों में अपने माता-पिता से मिल सकें, परन्तु इस रिवायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।
- (v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, शिक्षा-भत्ता।
- (vi) विदेश में सेवा के संबंध में सज्जा-भत्ता (Out fit Allowance) जो समय-समय पर सरकार द्वारा नियत की गई दरों पर और विहित नियमों के अनुसार मिलेगा। साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्त, बहुत ही ठंडी जलवायु वाले देशों में नियुक्त किए गए अधिकारियों को विशेष सज्जा-भत्ता भी मिल सकेगा।

- (vii) विहित नियमों के अनुसार, अधिकारियों और उनके परिवारों को छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ण) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगी। कुछ पड़ोसी देशों को छोड़, विदेश में की गई सेवा के लिए अधिकारियों को अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रिवायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष और समान हैसियत वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

(ठ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी समय-समय पर संशोधित, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 द्वारा और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होते हैं।

(ड) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी समय-समय पर संशोधित उदासीकृत पेंशन नियमावली 1950 द्वारा और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होते हैं।

19. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, भेनी II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतन-मान हैं—

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि वे शारीरिक स्वास्थ्य के अपेक्षित स्तर तक आते हैं या नहीं। पर यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को शारीरिक दृष्टि से अक्षम मान कर अस्वीकार कर सकती है और उसका निर्णय किसी भी प्रकार इन विनियमों से बंधा नहीं है। ये विनियम केवल मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए हैं और इनसे उसका निर्णय किसी प्रकार भी सीमित नहीं होता। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में इन मानकों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो

और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद वक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

कद	छाती का घेरा (पूरा फैला कर)	फैलाव	
	से०मी०	से०मी०	से०मी०
(1) *परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग	152	84	5
(2) **भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निको- बार द्वीप समूह	165	84	5

* (संख्या 1 में ऊपर जिस सेवा का उल्लेख किया गया है और उसमें छाती के घेरे पूरा फैलाकर माप के लिए जो मानक दिया गया है वह स्त्री उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा।)

** (स्त्री उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगा।)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम से कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जाएगा :—

यह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड्रियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ें सीधा खड़ा होगा और उसकी एड्रियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दि हेड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा

जाएगा और छायी का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84—89, 86—93.5 आदि नाम को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(i) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या विलक्षणता (एबनॉर्मैलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को ऐसा भेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटीगुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिससे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की संभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) :—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो जांचें की जाएंगी, एक दूर की नज़र के लिए और दूसरी नज़दीक की नज़र के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नज़दीक की नज़र का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नज़र				नज़दीक की नज़र	
अच्छी आंख				अच्छी आंख	
खराब आंख				खराब आंख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. परिवहन (याता-यात) और वाणिज्य विभाग 6/9 6/9 0.6 0.8
अथवा 6/6 6/12

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड II) श्रेणी-I, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I) भारतीय आर्दनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (महायक प्रबंधक, तकनीकी) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी-I, सैनिक भूमि और छावनी सेवा श्रेणी-I केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक सेवा, श्रेणी-II, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी-II					
		6/9	6/9	0.6	0.8
	अथवा	6/6	6/12		
3. भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II					
		6/9	6/9	0.6	0.8
	अथवा	6/6	6/12		

नोट :—

(1) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)-4.00 डी० से अधिक नहीं होगी, हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत) †4.00 डी० से अधिक नहीं होगी।

(2) ऊपर 2 में उल्लिखित सेवाओं के लिए मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)-8.00 डी० से अधिक नहीं होगी, कुल हाइपरमेट्रोपिया 6.00 डी० से अधिक नहीं होगी।

(3) फंडस परीक्षा—जब कभी संभव होगा मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जाएगी और पीण्डाम रिकार्ड किए जाएंगे।

(4) कलर विज़न—(i) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए रंगों के सम्बन्ध में नज़र की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर- (हायर और निम्नतर लोअर) ग्रेडों में होता चाहिए जो लैटर्न के द्वार (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	13 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

जनता की सुरक्षा से सम्बन्धित सेवाओं के लिए जैसे पाइलट, ड्राइवर, गाई आदि, के लिए कलर विजन का हायर ग्रेड अनिवार्य है लेकिन अन्य सेवाओं के लिए कलर विजन का लोअर ग्रेड ही काफी समझना चाहिए।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इन्हें प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज प्रीन की लैटर्न जैसी उपयुक्त लैटर्न और अच्छी रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

(5) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ़ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुख विधि (कन्फ़ॉर्मेशन मैथड) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(6) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़ कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(7) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कांडिशनस)—

(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वृत्त लुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोंहे (ट्रिकोमा):—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्विन्ट) ऊपर 1 और 3 में लिखी सेवाओं के लिए द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजमी

है। नियत स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दूसरी सेवाओं के लिए उस हालत में भेंगापन को अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए जब दृष्टि की पकड़ नियत स्टैंडर्ड की हो।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति:—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में डॉक्टर अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है:—

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टोलिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टोलिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्नर और विद्युत हृल्लेखी (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ़िक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (नीफ़रेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (बैकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढ़ा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 m.m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिम स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह मिस्टोलिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकालनी जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिम स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जायें, वह डायस्टोलिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इसमें रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल

कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस 'साइलेंट गेप' में रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए भूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के भूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और भधुमेह (डायबीटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों का भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निदिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्वान्टल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अक्षर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औपधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आप-रेशन) या ह्यूरिंग एंड इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हफलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफ़ी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रफ़र (हानिया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसोल, बड़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिक्बल) रोग है या नहीं।

10. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी

केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है। किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तमल्लो हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अंदर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करें तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इसमें सम्बन्धित मेडिकल प्रेक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बावजूद दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपॉइंटिंग ऑथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाइली इनफ़र्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहाँ प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सह-योजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए

जा सकते हैं किन्तु डाक्टरों बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहाँ डाक्टरों बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छंटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहाँ डाक्टरों बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड को राय भूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे डाक्टरों बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप में दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा:—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उस के साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौर, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरा कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को तपेदिक, स्कोफ्युला, गाऊट, दमा, दौर (फिट्स) मिरगी (एपिलेप्सी) या पागलपन (इन्सेनिटी) हुआ है ?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधोवृत्ति (नर्वसनेस) हुई है ?

7. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा दें ।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता का मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
--	--	--	--

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
--	---	---	---

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

9. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

11. कब और कहाँ मेडिकल बोर्ड हुआ ?

12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ।

मैं घोषित करता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे मामले हस्ताक्षर किए ।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जानबूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वाधक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेजुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) की शारीरिक परीक्षा की/ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें

1. सामान्य विकास : अच्छा बीच का कम
पोषण : पतला औसत मोटा
कद (जूते उतार कर) वजन
अत्युत्तम वजन कब था ?
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन
तापमान
छाती का घेर

(1) पूरा सांस खींचने पर
(2) पूरा सांस निकालने पर
2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी
3. नेत्र
(1) कोई बीमारी
(2) रतौंधी
(3) क्लर विजन का दोष
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन)
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्सिटी)

दृष्टि क. पद ड चश्मे को बना चश्मे से चश्मे का पावर

गोल सिलि० अक्ष

दूर की नजर दा० ने०
बा० ने०

पास की नजर दा० ने०
बा० ने०

हाइपरमेट्रोपिया दा० ने०
बा० ने०

4. कान : निरीक्षण

सुनेना :

दाया कान

बायां कान

5. ग्रंथिया थाइराइड

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरैटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सास के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दे ।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लज्ज) ?

गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर मिस्टानिक

डायस्टालिक

9. उदर (पेट) : घेर दाघ

वेदना (टेंडर्नेस) हनिया

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर

तिल्ली गुर्दे

ट्यूमर

(ख) बवासीर के मस्से

फिस्चुला

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत

11. चाल तंत्र (लोकामोटर सिस्टम)

कोई विलक्षणता

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटी यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसेल, बेरिकीसील आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा

(क) कैमा दिखाई पड़ता है

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षक गुणत्व)

(ग) एल्ब्यूमेन

(घ) शक्कर

(ङ) काम्ठ

(च) कोशिकाए (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिनके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं वा उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा का गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I और II

(ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखे) ।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखे) ।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II ।

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण

स्थान अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)

तारीख

सदस्य

सदस्य

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1966

सं० एफ० 16-6/65-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की 25 मई 1966 की अधिसूचना सं० एफ० 16-6/65-पी० ई० 4 के क्रम में

श्री आर० आई० एन० अहूजा,

सचिव, पंजाब सरकार

खेल विभाग, चण्डीगढ़

को

‘शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वेन्द्रेय संग्ठन के प्रशासन के लिए सोसायटी’ के गवर्नर्स बोर्ड के सदस्य के रूप में, इसी समय से तथा 16-8-1968 तक नामजद किया जाता है ।

रोशन लाल आनन्द, अवसर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1966

सं० 65 डब्ल्यू०डी०ओ०ओ०आर० 1/64—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिम रेलवे की उदयपुर-हिममतनगर मोटर लाइन (लम्बाई 209.80 किमीमीटर) 13-4-66 से यात्री-यातायात के लिए खोल दी गयी है ।

दिनांक 7 जून 1966

सं० 66 उद्यू० 1/सी० एन० एन०/एन०/2—मर्थ साधारण का सूचित्र किया जाता है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पीकरन जैमलमेर मोटर राइन रेल मम्पक के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस लाइन का लम्बाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इसका निर्माण उमर रेलवे द्वारा किया जाएगा।

इस निर्माण कार्य का नाम "पीकरन-जैमलमेर" रेल लाइन होगा।

पी० जी० मेथ्य, सचिव, रेलवे बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 जून 1966

राष्ट्रीय एकता और भावात्मक समन्वय पर सर्वोत्तम कथा (रूपक)

चित्र के नकव पुरस्कार

सं० 7/17/65-एफ०आई०—संकल्प संख्या 7/17/65 एफ० आई०, दिनांक 30 मार्च 1966 में आंशिक संशोधन करते हुए इसका पैरा 4 हटा दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० के० सामल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 जून 1966

सं० 7/16/63-एफ०आई० (एन० एन०)—एन० द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/19/64-एफ०आई० तारीख 21 नवम्बर 1964 में प्रकाशित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्बन्धी नियमावली के नियम 28 के अनुसार, सरकार ने निम्न-लिखित फिल्मों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है—

क्रम सं०	फिल्म का नाम	निर्माता/निर्देशक का नाम	पुरस्कार
	कथा चित्र	प्रादेशिक पुरस्कार	
1.	मलाजुह (उड़िया)	निर्माता श्री फिल्मम, मानसिंहपत्त,	राष्ट्रपति का रजत पदक।
		कटक-1।	
2.	का (उड़िया)	निर्माता श्रीमती पारबती घाय,	संस्कृता प्रमाण-पत्र।
		गंगामन्दिर,	
		कटक-1।	
		देशराज खन्ना, अवसर सचिव	

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 18th June 1966

No. 15/2/66-AIS(I).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October, 1966, for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the following services are with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information:

- The Indian Administrative Service,
- The Indian Foreign Service,
- The Indian Police Service,
- The Central Information Service, (Grade II), Class I,
- The Indian Audit & Accounts Service,
- The Indian Customs & Central Excise Service,
- The Indian Defence Accounts Service,
- The Indian Income-tax Service (Class I),
- The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers—Non-Technical),
- The Indian Postal Service, Class I,
- The Indian Railway Accounts Service,
- The Military Lands and Cantonments Service, Class I,
- The Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways,
- The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II,
- The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,
- The Customs Appraisers' Service, Class II,
- The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II,
- The Indian Foreign Service, Branch (B) Section Officers' Grade, Class II,
- The Railway Board Secretariat Service, Class II, and
- The Military Lands and Cantonments Service, Class II.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these services as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any service not specified by them.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services for which they wish to compete. No request for alteration in the order of preferences in respect of these Services will be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission or the Ministry of Home Affairs on or before 31st December, 1966.

2. Appointments shall be made on the results of the examination against permanent vacancies that may be reserved for

Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers in the following manner:—

Services	Percentage of vacancies reserved
(i) Indian Administrative Service/Indian Foreign Service	20%
(ii) Indian Police Service	30%
(iii) Central Services/posts, Class I (non-technical) (including those under the Railways)	25%
(iv) Central Services/posts, Class II (non-technical) (including those under the Railways)	30%

Provided that, in any recruitment year, the total number of vacancies reserved for the released EC/SSC officers in respect of this examination and for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in respect of the regular I.A.S. etc. Examination shall not exceed—

- in case of the I.A.S./I.F.S., and Central Services/posts Class I (non-technical), 45% of the total number of permanent vacancies to be filled by direct recruitment.
- in case of the I.P.S. and Central Services/posts Class II (non-technical), 50% of the total number of permanent vacancies to be filled by direct recruitment.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. All Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962, and who have been released/or are due to be released in the year 1967 will be eligible to appear at the examination provided they fulfil the qualifications/conditions prescribed in these Rules.

5. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India,

(2) For other services, a candidate must be either—

- citizen of India, or
- a subject of Sikkim, or
- a subject of Nepal, or
- a subject of Bhutan, or

- (c) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India, and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility, will be issued for a period of one year after which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories:—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6 (a) A candidate must *not* have attained the age of 24 years on the 1st August of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable:—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe; and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;
- (iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
- (ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;
- (xi) up to a maximum of three years in the case of the disabled Defence Services personnel; and
- (xii) up to a maximum of eight years in the case of the disabled Defence Services personnel who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

NONE OF THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

No candidate shall be permitted to compete more than four times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1966.

Provided that a candidate who had not attained the age specified in para 6 above on the 1st August of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces, but had attained that age on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training, shall be permitted to compete only once at the examination.

NOTE—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

8. A candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release.

A candidate who is eligible to take two chances must take the examinations held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

9. A candidate must have held a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must have possessed any of the qualifications mentioned in Appendix I-A at the time of joining pre-commission training in the Armed Forces.

Provided that a candidate for the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways must have possessed any of the above qualifications or any of the qualification mentioned in Appendix I-B at the time of joining pre-commission training in the Armed Forces.

NOTE 1 :—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who did not possess any of the foregoing qualifications at the time of joining pre-commission training in the Armed Forces, as a qualified candidate provided that he had passed examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

2 :—A candidate who was otherwise qualified at the time of joining pre-commission training in the Armed Forces but who had taken a degree from a foreign University which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

10. A candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of this examination will not be eligible to compete at a subsequent examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in col (ii) below on the results of this examination will be eligible to compete at a subsequent examination only for Services mentioned against that Service in col (iii) below :

S. No.	Service to which appointed	Services for which eligible to compete
(i)	(ii)	(iii)
1	Indian Police Service	I. A. S., I. F. S. and other Central Services, Class I
2	Central Services, Class I other than I.F.S.	I. A. S. I.F.S. and I.P.S.
3	Central Services, Class II, Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, and Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services, Class I

11. A candidate must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair

means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution.—

- (a) he debarred permanently or for a specified period :
 - (i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and
 - (ii) by the Central Government from employment under them;
- (b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *visa voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

18. (a) If on the results of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf from time to time.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application, but the Government of India reserve the right to assign him to any Service for which he is a candidate.

Provided that a candidate who is appointed to the I.A.S. or I.P.S. on the results of this examination will not be considered for allotment to any other Service on the results of a subsequent examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of this examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in col. (iii) below, on the results of a subsequent examination.

S. No.	Service to which appointed	Service to which allotment will be considered
(i)	(ii)	(iii)
1. Indian Police Service		I.A.S., I.P.S. and other Central Services, Class I.
2. Central Services, Class I other than I.P.S.		I.A.S., I.P.S. and I.P.S.
3. Central Services, Class II Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service and Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.		I.A.S., I.P.S., I.P.S. and other Central Services, Class I.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

23. No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

24. Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service Branch 'A' will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

O. S. MARWAH, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 9)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The Mandalay University.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Dublin.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sind.

The Rajshahi University.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 9).

1. French Examination "Baccalaureat."

2. French Examination "Propedeutique."

3. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.

6. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Tech. Education.

7. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."

8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

APPENDIX I-B

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways only (vide proviso to Rule 9).

(i) A pass in Sections A and B of the Associate membership examination of the Institution of Engineers (India); or such educational qualifications as are now or may subsequently be recognised by that institution as exempting candidates from passing Sections A and B of that examination; or

(ii) Associateship or Fellowship of the Indian Institute of Science, Bangalore; or

(iii) Hons. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the Loughborough College, Leicestershire, provided that a candidate has passed the common preliminary examination or has been exempted therefrom; or

(iv) A pass in Graduate Membership Examination of the Institution of Tele-Communication Engineers (India); or

(v) A pass in Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held after November, 1959.

The Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held prior to November, 1959, is also acceptable subject to the following conditions :—

(1) that the candidates who have passed the examinations held prior to November, 1959, should have appeared and passed in the following additional subjects :

(i) Principles and applications of Electrical Engineering (in accordance with the syllabus prescribed in Section A of Post-1959 Scheme).

(ii) Mathematics II (in accordance with the syllabus prescribed in Section B of Post-1959 Scheme).

(2) that the candidates concerned should produce a Certificate from the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) in fulfilment of the condition prescribed at (1) above.

APPENDIX II

Plan of the Examination

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 450 marks.

(b) *Viva Voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 250 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) Essay	3 hours	150
(ii) General English	3 hours	150
(iii) General Knowledge	3 hours	150

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule; and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular I.A.S. etc. Examination which will be held concurrently.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. From the marks assigned to candidates in each subject such deduction will be made as the Commission may consider necessary in order to secure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

(vide para 3 of Appendix II)

PART 'A'

1. *Essay*.—Candidates will be required to write an essay in English. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English*.—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually

be set for summary or précis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge*.—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian History, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART 'B'

Viva Voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The candidate will be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Services for which he has applied by a Board of Competent and unbiased observers.

The technique of the *viva voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate, e.g., mental alertness and initiative, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

APPENDIX III

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular I.A.S. etc. Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

1. *Indian Administrative Service*.—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000 (19 years).

Senior Scale :

(i) Time Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800. (25 years).

(ii) Selection Grade—Rs. 1,800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500 to which Indian Administrative service officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund*.—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave*.—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance*.—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules 1954.

(j) *Retirement Benefits*.—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service*.—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue

a course of training in India for approximately twenty one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted to various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund*.—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits*.—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service*.—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b) } As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian
(c) } Administrative Service.
(d) }

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of Pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300.

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,000—100—1,800.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—200—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,250.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 2,750.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(g) }
(h) } As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the
(i) } Indian Administrative Service.
(j) }

4. *Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II*.—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of pay :—

Grade I—Selection Grade.—Rs. 900 fixed.

Grade II—Time scale.—Rs. 300—25—475—EB—25—650—EB—30—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

5. *The Central Information Service, Grade II (Class I)*.—

(a) The Central Information Service consists of posts all over India, in various media organisations of the Ministry of

Information and Broadcasting, requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade	Rs. 2,250/- (Fixed).
Senior Administrative Grade	
(Senior Scale)	Rs. 1,800—160—2,400
(Junior Scale)	Rs. 1,600—100—1,800
Junior Administrative Grade	
(Senior Scale)	Rs. 1,300—60—1,600
(Junior Scale)	Rs. 1,100—50—1,400
Grade I	Rs. 700—40—1,100—50—1,250
Grade II	Rs. 400—40—450—50—600—35—670—EB—35—950.
Class II (Gazetted)	
Grade III	Rs. 350—25—500—50—550—LB—30—800
Class II (Non-Gazetted)	
Grade IV	Rs. 70—10—290—15—400—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies, as specified below, in the following grades of the Service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½%
Grade I	25%
Grade II	50%
Grade IV	100%

The remaining vacancies in the above grades and also vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade (Senior Scale) and Grade III are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication, on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration and a departmental test, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct-recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become efficient, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

6. Indian Audit and Accounts Service.

7. Indian Customs and Central Excise Service.

8. Indian Defence Accounts Service.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the department examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the Constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Officers under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of Pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the End-of-the-Course Test at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which, under the Department regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test against.

Indian Customs and Central Excise Service

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise Class I and Assistant Collectors of Central Excise	Rs. 400—400—450—30—510—LB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Assistant Collector of Customs.	
Deputy Collector of Customs	
Deputy Collector of Central Excise,	
Assistant Director	Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600
Deputy Director	
Additional Collector	
Appellate	
Collector of Customs,	Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.
Collector of Central Excise	

NOTE 1.—The probationers in the Indian Customs & Central Excise Service, Class I will draw pay in the prescribed scale of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie for a foundation course of training. At the end of the training at Mussoorie, they will have to pass the 'end-of-the-course test'. They will also have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course test' and Part I of the Departmental Examination their pay will be raised to Rs. 450.00. On passing Part II of the Departmental Examination, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480.00. The pay beyond the stage of Rs. 480.00 will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

2. In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE II.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs and Central Excise Service which the Government of India may think proper.

to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—
1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts.—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; 'provided further that in the case of an officer who does not pass the end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

9. *Indian Income-tax Service Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—
50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.

Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Commissioners of Income-tax

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Income-tax Training College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the I Departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subjected to such other conditions as may be found necessary.

In case, he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income Tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

10. *The Indian Ordnance Factories Service, Class I (Non-Technical Cadre).*—Appointments will be made to the posts of Assistant Manager (Non-technical). The candidate will be on probation for a period of two years during which period

he will undergo such practical training and pass such departmental and language tests as Government may prescribe.

On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

The selected candidates will be required to execute a bond at the time of his appointment that he will continue to serve in the Indian Ordnance Factories Service for a minimum period of three years after successful completion of his period of probation.

Assistant Managers, for whom the revised scale of pay is Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950, are eligible for promotion, on the basis of merit, to higher grades in the I.O.F.S., as shown below :—

	Scale of Pay
1. Deputy Manager (Non-Technical)/ Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 700—40—1,100 —50/2—1,250.
2. Manager (Non-Technical)/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,100—50—1,400
3. Assistant Director General, Or- dnance Factories (Grade II).	Rs. 1,300—60— 1,600.
4. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade I).	Rs. 1,600—100— 1,800.
5. Deputy Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,800—100— 2,000.

11. *Indian Postal Service (Class I).*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Time Scale :—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—
40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800—100—2,000.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,250.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, Class I, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie, they will have to pass the 'end of the course test'. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end of the course test' and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end of the course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the Departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, Class I, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

12. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months' notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for

confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo a course of training at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the test prescribed by the College authorities. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the test at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Pravcen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the leave rules for the time being in force as applicable to officers of Indian Railways.

The leave rules are, however, liable to revision in the light of the Pay Commission's recommendations. They will not be permitted to retain the present leave rules, if so decided by the Government.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(i) Scales of pay :—

(1) Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250 (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250 (Authorised Scale).

(b) On appointment a probationer shall execute an agreement binding himself and one surety jointly and severally to refund in the event of his failing to complete probation to the satisfaction of the Central Government, any moneys paid to him consequent on his appointment as probationer.

(c) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer

will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their services for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationers will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

13. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).*

(a) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under sub-para. (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing, provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing of the departmental examination.

(f) In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

Administrative Posts

(i) Director, Military Lands and P., 1,800—100—2,000 Cantonments.

(ii) Joint Director, Military Lands P., 1,600—100—1,800 and Cantonments.

(iii) Deputy Director, Military P., 1,300—60—1,600 Lands and Cantonments.

(iv) Assistant Director, Military P., 1,100—50—1,400 Lands and Cantonments.

Class I

(v) Deputy Assistant Director, P., 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. Military Lands and Cantonments, Military Estate Officers and Executive Officers.

Class II

(vi) Executive Officers P., 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.

(vii) Assistant Military Estates P., 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Officers.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable. (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

14. Transportation (Traffic) and Commercial Department of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways.

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Transportation (Traffic) and Commercial Department for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (n) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Transportation (Traffic) and Commercial Department wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should, as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination, both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) On appointment, a probationer shall execute an agreement binding himself and one surety jointly and severally to refund in the event of his failing to complete probation to the satisfaction of the Central Government, any moneys paid to him consequent on his appointment as probationer.

(e) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(f) Officers (including probationers) of the Transportation (Traffic) and Commercial Department of the

Superior Revenue Establishment of Indian Railways recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund as amended from time to time.

(g) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

(h) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

The Leave Rules are liable to revision in the light of the accepted recommendations of the Pay Commission. They will not be permitted to retain the present Leave Rules, if so decided by the Government.

(i) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

(j) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily, the officer will be liable to lose in seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

(k) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that or which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

(l) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department

(m) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

(n) Courses of training for probationers in the Transportation (Traffic) and Commercial Department.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case

of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

(1) Length of course—two years.

Item	Period
1. National Academy of Administration, Mussoorie	4 month(s)
2. Area School, to learn Guard's duties	1 "
3. Working as Guard	½ "
4. Training in Baroda Staff College (1st phase)	3 "
5. Booking Office, Parcel Office, Goods Shed and Transshipment shed	1 "
6. Traffic Accounts including a period with the Travelling Inspector of Accounts & personal preparation of balance sheets at stations	1½ "
7. Area School to qualify as Asstt. Station Master	1 "
8. Working as Yard Master, Asstt. Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	3 "
9. Working as Asstt. Loco Foreman	½ "
10. Working as Assistant Controller	2 "
11. Training at Baroda Staff College (IInd phase)	1½ "
12. (a) Training in District or Divisional Office	1 "
(b) Training as Assistant Power Controller	½ "
13. Training in Headquarters Office (Operating)	1½ "
14. Training in Headquarters Office (Commercial)	1½ "
	23½ "
Periods set apart for journey time for taking up various items for training & inescapable leave	½ "
TOTAL	24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years' training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

15. *The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II—*

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades:—

Grade	Scale of Pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent	Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.
Grade I—Under Secretary	Rs. 900—50—1,250.
Section Officers' Grade	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistants Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530

Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry of Home Affairs on an all-Secretariat basis. Section Officers'/Assistants' Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be in charge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. *Customs Appraisers' Service, Class II—*

(a) The prescribed scale of pay is Rs. 350—25—500—30—590—E.B.—30—800—E.B.—35—900. Officers recruited direct to this service will be on probation for two years, during which period they will undergo such training and pass such departmental test as may be prescribed by the Central Board of Excise and Customs. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test will result in the discharge of the probationer from service.

(b) On the conclusion of the period of probation and the successful passing of the Departmental Test the Officers will be eligible for confirmation subject to the availability of permanent post. If his work or conduct has, in the opinion of the Collector of Customs concerned, been unsatisfactory he may be discharged from service or his period of probation may be extended as the Collector of Customs concerned, may think fit.

(c) After a period of Service as Appraisers the Officers will be eligible for promotion to the Grade of Principal Appraiser in the scale of Rs. 600—35—950—and thereafter to the posts of Assistant Collectors, Class I.

(d) As regards leave, pension and other conditions of service, they will be treated like other Class II Officers.

NOTE.—The scales of pay and grades given above are liable to revision.

17. *Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay—

Grade I—Selection Grade—Rs. 900—50—1,200.

Grade II—Rs. 300—30—510—EB—30—600—40—720—EB—40—800—50—850.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get Dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. The Railway Board's Secretariat Service, Class II—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

Service	Scales of Pay
(i) Assistant Director /Under Secretary.	Rs. 900—50—1250.
(ii) Section Officer	Rs. 350—25—500—50— 590—EB—30—800— EB—30—830—35— 900.
(iii) Assistant	Rs. 210—10—270—15— 300—EB—15—450— EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers who have acquired sufficient experience by working in the sections in the Secretariat will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be incharge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligible for appointment to higher posts in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that fund as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

19. Indian Foreign Service, Branch 'B', Section Officers' Grade Class II—

(a) 25% of the maintenance vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—E. B.—30—800—E. B.—30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government, been unsatisfactory, may either discharge him from the service, or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clauses.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Commerce and Industry they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While Serving in India Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS(B) in the scale of Rs. 900—50—1250, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the General Cadre of the IFS(B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of the IFS(A) in the scale of pay of Rs. 900 (6th year or under)—50—1000—60—1600—50—1800, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce and Industry. They are, however, liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During Service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned in from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFP(PLCA) Rules, 1961, as made applicable to I.F.S.(B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passages to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18, studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

(j) The revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(k) While in India, Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

APPENDIX IV

Regulations Relating to the Physical Examination of Candidates

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. But it must be clearly understood that the Government of India reserve to themselves an absolute discretion to reject as unfit any candidate whom they may consider on the report of the Medical Board, to be physically disqualified and that their discretion, is in no respect limited by these regulations. These regulations are intended merely for the guidance of Medical Examiners and are not meant to restrict their discretion in any way. For the disabled Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
* (1) Transportation (Traffic) and Commercial Department	152 cms	84 cms	5 cms
** (2) Indian Police Service, Delhi and Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II	165 cms	84 cms	5 cms.

*[The standard of chest girth/expansion prescribed for the service mentioned at (1) above will not apply to women candidates].

** (Not applicable to women candidates).

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwals, Assamese, Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of a half of a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) *General*.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity*.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

	Distant vision		Near vision	
	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
1. Transportation (Traffic) and Commercial Department	6/9 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8
2. I.A.S., I.F.S., Central Information Service (Grade II), Class I, Indian Audit & Accounts Service, Indian Customs & Central Excise Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Income-tax Service, (Class I), Indian Ordnance Factories Service, Class I (Assistant Managers—Non-Technical), Indian Postal Service, Class I, Indian Railway Accounts Service, Military Lands and Cantonment Service, Class I, Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II, Customs Appraisers Service, Class II, Delhi & Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II, Railway Board Secretariat Service, Class II Military lands and Cantonment Service, Class II	6/9 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8
3. Indian Police Service and Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Class II)	6/9 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8

NOTE :—

(1) In respect of Services mentioned at 1 and 3 above. Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4.00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

(2) In respect of services mentioned at 2 above. Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —8.00D. Total Hypermetropia shall not exceed +6.00D.

(3) *Fundus Examination*.—Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(4) *Colour Vision*.—(i) The testing of colour vision shall be essential in respect of services mentioned at 1 and 3 above

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidates	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1.3 mm.	13 mm.
3. Time of exposure	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with the safety of the Public, e.g., pilots, drivers, guards etc., the higher grade of colour vision is essential but for other the lower grade of colour vision should be considered sufficient.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(5) *Field of vision*.—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(6) *Night Blindness*.—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of nightblindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(7) *Ocular conditions other than visual acuity*.—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma*.—Trachoma, unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint*.—For services mentioned at 1 and 3 above where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For the other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(d) *One-eyed persons*.—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic press is as follows :—

- With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.
- With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The

cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. The following additional points should be observed :—

- that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services;
- that his/her speech is without impediment;
- that his/her teeth, are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);
- that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;
- that there is no evidence of any abdominal disease;
- that he is not ruptured;
- that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocoele, varicose veins or piles;
- that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;
- that he does not suffer from any inveterate skin disease;
- that there is no congenital malformation or defect;
- that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;
- that he bears marks on efficient vaccination; and
- that he is free from communicable disease.

10. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place
3. (a) Have you ever had small-pox, Intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis?
- Or
- (b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?
4. When were you last vaccinated?
5. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption, scrofula, gout, asthma, fits, epilepsy, or insanity?
6. Have you suffered from any form of nervousness due to over-work or any other cause?

7. Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death
--	--	--	--

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death
--	--	---	--

8. Have you been examined by a Medical Board Before?
9. If answer to the above is Yes, please state what Service/Services you were examined for?
10. Who was the examining authority?
11. When and where was the Medical Board held?
12. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate)
physical examination

1. General development: Good.....Fair.....
Poor.....
 - Nutrition: Thin.....Average.....Obese.....
 - Height (Without shoes)Weight.....
 - Best Weight..... When ?.....Any recent change
in weight ?.....Temperature.....
 - Girth of Chest.
(1) (After full inspiration)
(2) (After full expiration)
 2. Skin: Any obvious disease.....
 3. Eyes:
(1) Any disease.....
(2) Night blindness.....
(3) Defect in colour vision.....
(4) Field of vision.....
(5) Visual acuity.....
- | Acuity of vision | Naked
eye | With
glasses | Strength of
Sph. Cul. Axis |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| Distant vision | R.E.
L.E. | | |
| Near vision | R.E.
L.E. | | |
| Hypermetropia
(Manifest) | R.E.
L.E. | | |
4. Ears: Inspection.....Hearing: Right Ear.....
Left Ear.....
 5. Glands.....Thyroid.....
 6. Condition of teeth.....
 7. Respiratory System: Does physical examination reveal
anything abnormal in the respiratory organs ?.....
If yes, explain fully.....
 8. Circulatory System:
(a) Heart: Any organic lesions ?.....Rate
Standing.....
After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....
(b) Blood Pressure : Systolic.....
Diastolic.....
 9. Abdomen : Girth.....Tenderness.....
Hernia.....
(a) Palpable: Liver.....Spleen.....
Kidneys.....Tumours.....
(b) Hemorrhoids.....Fistula.....
 10. Nervous System: Indication of nervous or mental dis-
abilities.....
 11. Loco-Motor System: Any abnormality.....
 12. Genito Urinary System: Any evidence of Hydrocele. Vari-
cocele etc.
Urine Analysis:
(a) Physical appearance
(b) Sp. Gr.
(c) Albumen.....
(d) Sugar.....
(e) Casts.....
(f) Cells.....
 13. Report of X-Ray Examination of Chest.
 14. Is there anything in the health
of the candidate likely to render
him unfit for the efficient dis-
charge of his duties in the
service for which he is a candi-
date?

15. (i) State the Service for which
the candidate has been exa-
mined:—

(a) IAS & IFS.....

(b) IPS & Delhi Himachal
Pradesh and Andaman
and Nicobar Islands
Police Service.....

(c) Central Services, Class I
& II.....

(ii) Has he been found qualified
in all respects for the efficient and
continuous discharge of his duties
in:—

(a) IAS & IFS.....

(b) IPS and Delhi Himachal
Pradesh and Andaman
and Nicobar Islands
Police Service.....

(see especially height,
chest girth, eye sight,
colour blindness and lo-
comotive system).

(c) Transportation Traffic &
Commercial Department
of the Indian Railways..
(see especially height,
chest, eye sight, colour
blindness).

(d) Other Central Services
Class I/II.....

(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE.—The Board should record their findings under one
of the following three categories:

(i) Fit

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporary unfit on account of.....

Place

Date

Chairman

Member

Member

New Delhi, the 4th June 1966

No. 26/3/65-P.III.—In exercise of the powers conferred by
the proviso to article 309 of the Constitution, the President
hereby makes the following rules further to amend the Central
Police Training College (Gazetted Staff) Recruitment Rules,
1959, namely:—

1. (i) These rules may be called the Central Police Training
College (Gazetted Staff) Recruitment (Amendment)
Rules, 1966.

(ii) They shall come into force on the date of their pub-
lication in the official Gazette.

2 In the Schedule to the Central Police Training College
(Gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, in column
4 for the existing entry against item No. 3A, relating
to Senior Instructor, the following shall be substituted
namely:—

“(i) Sr. scale of IP/IPS plus a special pay of
Rs. 200/- (for IP and IPS Officers).

(ii) Pay and special pay (if any) to be fixed on
ad hoc basis—(for other officers)”,

G. L. BAILUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-1, the 30th April 1966

No. 10/6/65-SR.—For the name “Shri A. P. Mitra” appear-
ing at serial No. 6 in this Department's notification No.
10/6/65-SR dated April 1, 1966 the following may be
substituted:—

“Dr. A. P. Mitra”

S. V. RAGHAVAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE*New Delhi, the 2nd June 1966***AMENDMENT**

No. 35(2)Com-Genl(FMC)65.—In paragraph 1 of this Ministry's Resolution No. 35(2)Com-Genl(FMC)65, dated the 16th February 1966, the following addition may be made before the name of Shri R. Mahadevan, Deputy Financial Adviser, Ministry of Finance, New Delhi.

Prof. S. V. Kogekar, —Member
Member,
Forward Markets Commission,
Bombay.

ORDER

ORDERED that the amendment be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. K. SACHDEV, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**RESOLUTION***New Delhi, the 27th May 1966*

No. 4-20/66-FP.(Estt. F.P).—In partial modification of the Government of India, Ministry of Health (now Ministry of Health & Family Planning) Notification No. 1-49/62-H.II(FP) dated the 13th September 1962, regarding the reconstitution of the Governing Body of the Demographic Training and Research Centre, Bombay, it is resolved that the Secretary, Department of Family Planning in the Ministry of Health and Family Planning shall be member of the Governing body of the Demographic Training & Research Centre instead of the Secretary, Ministry of Health as mentioned at S. No. 2 of the Notification.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, all members of the Demographic Training and Research Centre, Bombay, all Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission, Prime Minister's Secretariat, Parliamentary Secretary and Department of Parliamentary Affairs.

ORDERED that it be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)***New Delhi, the 3rd June 1966*

No. 65/WDO/ORI/64.—It is hereby notified for general information that the new Metre Gauge line between Udaipur City and Himmatnagar a length of 209.80 Kilometers on the Western Railway has been opened for the public carriage on 13-4-66.

The 7th June 1966

No. 66/W4/CNL/N/2.—It is hereby notified for general information that the Ministry of Railways (Railway Board) have sanctioned the construction of Pokaran-Jaisalmer metre gauge Rail Link. The length of the line is about 105 KMs. The construction work will be carried out by the Northern Railway.

The construction will be known as POKARAN-JAISALMER rail line.

P. C. MATHEW, Secy., Railway Board

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING**RESOLUTION***New Delhi-1, the 4th June 1966*

Cash Prize for the best feature film on national unity and emotional integration

No. 7/17/65-FI.—In partial modification of Resolution No. 7/17/65-FI dated 30th March 1966, para 4 thereof may be deleted.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. SAMAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION**(Department of Labour and Employment)****RESOLUTION***New Delhi, the 4th June 1966*

No. WB-3(4)/66.—By their Resolution No. WB-3(12)/59, dated the 5th December 1960, the Government of India appointed a Central Wage Board for Tea Plantation Industry, with the following composition and terms of reference :—

I Composition**Chairman**

Shri L. P. Dave.

Independent Members

Shri T. Manan M.P.

Dr. R. Balakrishna

Members representing employers

Shri L. T. Garmichael.

Shri J. B. Soutar.

Members representing workers

Shri G. Ramanujam.

Shri B. Bhagwati.

Some changes in the membership of the Board became necessary in the course of time and these were notified

II. Terms of Reference

To work out a wage structure based on the principles of fair wages as set forth in the report of the Committee on Fair Wages as far as practicable.

In evolving a wage structure, the Board should, in addition to the considerations relating to fair wages, also take into account :—

- (i) the needs of the industry in a developing economy.
- (ii) the system of payment by results;
- (iii) the special characteristics of the industry in various regions and areas;
- (iv) categories of workers to be covered (this may be according to the definition of workmen in the Industrial Disputes Act);
- (v) working hours in the industry;

Explanation.—Whenever applying the system of payment by results the Board shall keep in view the need for fixing a minimum (fall-back) wage and also to safeguard against overwork and undue speed.

2. The recommendations made by the Wage Board for the grant of interim wage increases were accepted by Government and the parties were advised to implement them.

3. The Board's final report was received by Government on the 31st May 1966. The recommendations, as summarised by the Board, are appended. Copies of the report will be made available for sale through the Manager of Publications in the usual course.

4. The Board's recommendations are unanimous on most points although minutes of dissent on certain matters have been appended both by the employers' and workers' representatives on the Board. The Chairman and independent members have also added a note clarifying the position in regard to the points made out in the notes of dissent recorded by the employers' representatives. After careful consideration, the Government have decided to accept the Board's recommendations and to request the employers, the workers and the State Governments to implement the same expeditiously.

5. The Government do not propose to express any views on the matters raised in the dissenting notes. As agreement has been reached on the broad issues, the Government hope that differences, if any, over matters of detail and/or minor issues will be settled by the parties in mutual negotiation or by voluntary arbitration.

6. The Government of India wish to express their appreciation of the work done by the Board and to convey their thanks to the chairman and members of the Board.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

APPENDIX**SUMMARY OF BOARD'S RECOMMENDATIONS****(1) Extent of tea industry covered**

Recommendations should apply to all tea plantations in which tea is being cultivated, produced and/or manufactured for commercial purposes (Paragraph 4.1).

(2) Categories of employees covered

All workers employed in tea plantations in fields, factories, workshops, offices, hospitals (including group hospitals), dispensaries, schools, welfare establishments, etc. in the tea plantations or connected with them and coming within the definition of 'workman' in clause(s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 should be covered by the Board's recommendations. All employees in tea plantations, whether they work on the plantation itself or at any place in the tea

plantation district would also be covered. But employees working in any office situated at district or sub-divisional headquarter town would not be covered by the Board's recommendations (Paragraph 4.2).

(3) Daily rates of wages for field workers

The daily wages of workers should consist of basic wage and dearness allowance. The basic wage of field workers should be as mentioned in the statement given below :

Basic Rates of wages

(In Rs. P.)

State	Region	Basic wage effective from					
		1-1-66			1-4-66		
		Men	Women	Children	Men	Women	Children
A. North East India.							
1. Assam	Dibrugarh sub-Division of Lakhimpur district and Sibsagar district.						
(i) Assam Valley	(i) Tea Plantations of 150 acres and above*	2.23	2.05	1.08	2.25	2.07	1.09
	(ii) Other tea plantations	2.20	2.02	1.07	2.22	2.04	1.08
	Darrang district (except Mangaldai) and North Lakhimpur sub-division of Lakhimpur district.						
	(i) Tea plantations of 150 acres and above..	2.16	1.99	1.05	2.18	2.01	1.06
	(ii) Other tea plantations	2.13	1.96	1.04	2.15	1.98	1.05
	Mangaldai in Darrang district.						
	*United North Cachar & Mikhir Hills, Nowgong, Kamrup and Goalpara districts	2.06	1.95	1.04	2.08	1.97	1.05
(ii) Cachar	Cachar and tea plantations within 10 miles area of Dimapur.*	1.70	1.60	0.91	1.72	1.62	0.92
2. West Bengal							
	Dooars						
	For tea plantations of 500 acres and above	2.11	1.94	1.14	2.13	1.96	1.15
	For tea plantations below 500 acres	2.08	1.91	1.14	2.10	1.93	1.15
	Teral and Cooch Bihar	2.05	1.88	1.12	2.07	1.90	1.13
	Darjeeling*	1.73	1.62	0.94	1.75	1.64	0.95
3. Tripura	Tripura	1.51	1.32	0.74	1.53	1.34	0.75

*These rates are subject to the condition that no reduction from the present wage rates will be made.

State	Region	Basic wage effective from		
		1-1-66		
		Men	Women	Children
<i>B. North India</i>				
1. Punjab and Himachal Pradesh	Kangra and Mandi	1.20	0.94	0.55
2. Uttar Pradesh	Dehradun	1.60	1.60	—
	Bering and Chokorie areas of Almora district.	1.20	1.20	—
	Other areas of Almorah and Garwal district	0.86	0.86	—
3. Bihar	Ranchi	1.55	1.55	—

C. South India

State	Categories of estates	Basic wage effective from			
		1-1-66			
		Men	Women	Adolescents	Children
1. Madras	100 acres and above	2.25	1.80	1.35	1.13
	Less than 100 acres	2.11	1.66	1.29	1.14
2. Kerala	100 acres and above	2.25	1.80	1.35	1.13
	Less than 100 acres	2.18	1.76	1.33	1.11
3. Mysore	100 acres and above	2.25	1.80	1.35	1.13
	Less than 100 acres	2.11	1.64	1.25	1.13

(4) *Daily rates of wages for factory workers*

Existing differentials between rates of wages of field workers and factory workers in North East India will continue. With effect from 1-1-1966 factory workers (in Madras, Kerala and Mysore) are to be paid a differential over the new daily wage rates of the field workers at the following rates:

Men	20 paise over field men's wage.
Women	15 paise over field women's wage.
Adolescents	15 paise over field adolescent's wage.

(Paragraph 4.7)

(5) *Wages of pruners, sprayers, etc.*

The present differentials, if any, between the wages of workers employed in pruning, spraying, etc. and those employed in ordinary field work should continue (Paragraph 4.8).

(6) *Wages of supervisors/maistries (in South India)*

The supervisors/maistries should be paid wage increase from 1st January 1966 equal to the wage increase granted to an adult male workers in the field from the same date plus 20 per cent of the differentials existing between the total wages of supervisors/maistries as on 31st December 1965 and the wages of adult male workers in the field on the same date. In the case of kole maistries in South India, the increase is to be 6 paise per day plus the increase given to adult male workers. (Paragraph 4.9).

(7) *Dearness Allowance*

The dearness allowance is to vary in North East 0.4 paise and in North India and South India @ .75 paise per day per point of increase (above 170 points) in the average All India consumer price index number subject to a maximum increase of 16 points in North East India and South India or (6 paise in North East India) and 12 points in North India in any one calendar year. Any excess over this limit, in any year, up to the level of 200 points, is to be carried over to the following year. No dearness allowance revision beyond 200 points before 31st December 1970. Dearness allowance to be rounded off at the end of each month (Paragraphs 4.10 to 4.15).

(8) *Piece rates*

(i) In North East India the existing system of piece rates, particularly plucking rates, should continue but may be revised by agreement between employers and labour so that the worker with normal diligence would earn at least the fair wages now agreed to for a day of 8 hours work (Paragraph 4.16).

(ii) In South India the existing system of piece rates in Kerala, Mysore and Madras should continue. The rates should however be revised so as to be in step with the increase agreed to for the daily rated workers (Paragraph 4.17).

(9) *Mixed estates*

Wages of workers in mixed estates in South India should be governed by existing practice. (Paragraph 4.18).

Staff Wages(10)(a) *North East India**Wage increase from 1-1-1966*

From 1-1-1966 the clerical and medical staff and technicians should be granted increase in their cash emoluments payable for the month of December 1965 at 52 times the rate of increase granted to the daily rated workers, with effect from 1-4-1966 in the region. The other monthly rated workers should be similarly granted increase at 33 times the increase granted to the daily rated workers in the region (Paragraphs 4.19 & 4.20).

(11) *Wage structure from 1st April 1966*

(i) The following should be the basic pay scales for the various grades of staff employed in tea plantations in North East India, with effect from 1st April, 1966 :—

Grade	For estates of 300 acres and above	Other estates
A. Clerical Staff		
	Rs.	Rs.
I.	220—8—300—10—400	150—6—210—7—280
II.	160—6—220—8—300	110—4—150—5—200
III.	125—4—165—5—190—6—220.	90—3—120—4—160
B. Medical staff		
I.	250—15—400—EB—20—600.	220—8—300—12—480
II.	160—7—230—10—330	120—4—160—5—235

Grade	For estates of 300 acres and above	Other estates
	Rs.	Rs.
III.	130—5—180—7—250	90—3—120—4—180
C. Artisans and Technicians		
A.	210—8—290—10—390	180—8—260—10—360
B.	150—6—210—7—280	130—6—190—7—260
C.	100—3—130—4—170	80—3—110—4—150
D. Subordinate and monthly rated staff		
I.	80—3—140	80—3—140
II.	70—2—110	70—2—110
III.	60—2—100	60—2—100

(ii) In the case of tea plantations of less than 150 acres, grade I in the case of staff and grade A in the case of artisans and technicians will not apply. (Paragraphs 4.21, 4.22 and 4.23).

(iii) All gardens between 151 and 450 acres in Darjeeling, Cachar, Tripura, North Cachar and Mikir Hills will pay the scales prescribed for gardens of less than 300 acres in these districts. (Paragraph 4.23 A).

(iv) For gardens in Darjeeling above 450 acres, the scales for gardens over 300 acres will apply but grade I in the case of clerical staff and grade A in the case of technicians will not apply. (Paragraph 4.23 A).

(12) *Categorisation*

Clerical and medical staff, and artisans and technicians, subordinate staff and other categories of employees in North East India are to be categorised and fixed in the New grades according to the rules prescribed. (Paragraphs 4.23 A and 4.24).

(13) *Fitment in the new scales of pay*

Fixation of employees in new scales of pay should be according to the conditions laid down. (Paragraph 4.25).

(14) *Phased implementation of wage rise*

In the case of employees who are much below the starting basic pay of the new scales, the maximum increase in basic pay would be Rs. 10 per year plus the equivalent of one increment in the new scales until the starting pay of the new scales is reached. The increments, where necessary, should take effect from 1st April 1966. New recruits are to start with basic pay one increment lower than the lowest paid employee of the same category in an estate. (Paragraph 4.26).

(15) *Conversion of daily rated into monthly rated*

For conversion from daily rated into monthly rated, the daily rates should be multiplied by 26 for fixing the pay in the new scale (Paragraph 4.27).

(16) *Dearness Allowance*

The fixed dearness allowance, with effect from 1st April 1966, should be 20% of the new basic pay. The variable dearness allowance should be @ 0.4 per cent of the new basic pay per point rise above 170 in the All India consumer price index, for clerical, medical and technical staff and @ 0.3 per cent per point rise for subordinate and monthly rated staff subject to a maximum of 16 points in any calendar year. Any excess over this limit in any year up to the level of 200 points is to be carried over to the following year. No dearness allowance revision beyond 200 points before 31st December 1970 (Paragraphs 4.28 to 4.31).

(17) *Servant Allowance*

Subject to higher rate of servant allowance remaining unaffected and present grade C artisans (who are in receipt of this allowance at present) continuing to get it as personal pay, the servant allowance, wherever it is payable at present, should be at the following rates, with effect from 1-4-1966 :

Plantation less than 300 acres	Other Plantations
Rs. 35 per month from 1-4-66	Rs. 35 p.m. from 1-4-1966
	Rs. 40 p.m. from 1-4-1967
	Rs. 45 p.m. from 1-4-1968
	Rs. 50 p.m. from 1-4-1969
	Rs. 55 p.m. from 1-4-1970

The servant allowance is to be regarded as part of basic pay for purpose of overtime payment, provident fund contribution and bonus (Paragraph 4.32).

(b) *North India*(18) (i) *Pay scales*

The new pay scales in North India tea Plantations with effect from 1st April 1966, should be :

- (1) Minimum grade for staff Rs. 90—3—120—4—160
- (2) Minimum grade for sub-staff Rs. 60—2—100.

(Paragraph 4.34)

(ii) *Dearness Allowance*

The fixed and the variable dearness allowance are to be at the same rates as in North East India (Paragraph 4.36).

(19) *Categorisation and fitment*

Categorisation and fitment of staff in North India are to be according to the principles laid down (Paragraphs 4.35 and 4.37).

(c) *South India**

(20) In South India the pay scales, dearness allowance, servant allowance, categorisation and fitment (given below) are the same as modified by Staff Settlement dated 4th May 1965. (Paragraph 4.38).

(1) *Scales of pay with effect from 1-1-1966**Large Estates in all the three States*

General Grade	Rs. 40/50—3—56—4—80—FB—5—120—LB—6—180
Senior Grade 'A'	Rs. 90—6—120—LB—7—148—LB—8—196—200
Senior Grade 'B'	Rs. 150—10—280.

Medium Estates in Madras and Kerala

General Grade	Rs. 40—50—3—56—4—80—FB—5—130
Senior Grade (For heads of Depts. only)	Rs. 90—5—120—EB—7—148—EB—8—180—10—220

Medium 'B' Estates in Mysore

General Grade	Rs. 40/50—3—60—4—80—EB—5—135
Senior Grade	Rs. 90—6—120—FB—7—148—LB—8—196

Medium 'A' Estates in Mysore

General Grade	Rs. 40—3—55—4—75—EB—5—105
Senior Grade	Rs. 90—5—120—EB—6—156

NOTE—The definition of large, medium, medium 'A' and medium 'B' estates are the same as in the Staff Settlements of 1957 and 1958.

(ii) *Categorisation, fitment and promotions*

(21) According to the provisions in the Staff Settlement dated 4th May 1965 (Paragraph 4.38).

(iii) *Dearness Allowance*

(22) The dearness allowance, with effect from 1-1-1966 is to be according to the UPASI revised scales of Dearness Allowance; a schedule of which is attached to Staff Settlement dated 4th May 1965 (Paragraph 4.38).

(iv) *Servant Allowance*

(23) Servant allowance @ Rs. 35, except in the case of general grade in small A estates in Mysore, where it is Rs. 17.50 per month (Paragraph 4.38).

(24) *Promotion procedure in certain cases (in North East India)*

Promotion in certain cases such as those of nurses without nursing certificate, medical staff of grade III, subordinate staff reaching top of their grades and grade C artisans, are to be according to the procedure laid down (Paragraph 4.33).

*Note of dissent.

(25) *Relief in certain cases*

Cases of members of the staff reaching maximum of the new scales, as a result of Board's proposals, are to be considered by the industry sympathetically for giving relief (Paragraph 4.38 A).

Miscellaneous(26) *Period of Enforcement*

Recommendations to remain in force from 1st January 1966 to 31st December 1970 in respect of Labour in the entire country and from 1st April 1966 to 31st March 1970 in respect of staff in North East India. The revised wages for staff in South India, are to remain in force from 1st January 1965 to 31st December 1969. (Paragraph 4.39).

(27) *Splitting of Tea Estates*

Splitting of a tea estate is not to affect wage rates (Paragraph 4.40).

(28) *Employment of Family Members*

Whenever extra hands are to be engaged, members of workers family are to be given preference (Paragraph 4.42).

(29) *Supply of foodgrains*

All tea plantations in India should be supplied with foodgrains regularly by Government and the employers should supply the same in North East India at the existing concessional prices or at such rates as may be revised by agreement between the parties and in South India on 'no profit no loss' basis, in addition to providing rent free storage and free clerical and other services for distribution. (Paragraph 4.44).

(30) *Revision of Prices of Cereals*

The question of revision (upgrading) of concessional prices of cereals in North East India may be discussed on regional basis between employers and labour. The quantities and prices should be switched on to metric system (Paragraph 4.45).

(31) *Cold Weather Tasks in North East India*

Parties may make such adjustments in cold weather tasks as can be performed by a worker of normal diligence in 7 to 8 hours, by mutual agreement (Paragraph 4.46).

(32) *Existing Amenities, Benefits etc. to Remain Unaffected*

Board's recommendations are without prejudice to the existing amenities and benefits and the concessional supply of foodgrains in North East India. (Paragraph 4.47).

(33) *Payment of Arrears*

If back wages accumulate for a period exceeding 6 months, the industry is to be allowed to pay the accumulated wages in two equal instalments, one within one month of the date of publication of the Government notification and the other within another month. (Paragraph 4.48).

(34) *"Constitution of Committees—Committees are to be constituted with equal representatives of workers and employers organisations with Labour Commissioner of the respective State as Chairman to go into the difficulties of over-staffed or otherwise handicapped gardens in North East India due to partition of India and other allied reasons and to devise remedial measures"* (Paragraph 4.23B).

(35) *Machinery for Interpretation*

Disputes arising out of the interpretation of the Board's recommendations are to be decided by arbitration of a sitting or retired High Court Judge, whose decision would be final and binding upon the parties (Paragraph 4.49).